

प्रक.

आर०के० विश्व

अपर सचिव

उत्तराखण्ड शासन.

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक

नियोजन एवं वित्तीय प्रबंधन,

उत्तराखण्ड, देहरादून.

वन एवं पर्यावरण अनुभाग-2

देहरादून दिनांक > 1 फरवरी, 2008

विषय:- अनुदान संख्या-27 आयोजनागत पक्ष की योजना " वन विभाग के आवासीय तथा अबावासीय भवनों का निर्माण" योजना के अवधार्त वर्ष 2007-08 में प्रस्तावित कार्यों की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति.

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या-नि.333/35-1-बी, दिनांक 31 अगस्त, 2007, पत्र संख्या-नि.461/35-1-बी, दिनांक 26 सितम्बर, 2007 तथा पत्र संख्या-वि.797/35-1-बी, दिनांक 13 दिसम्बर, 2007 के क्रम में मुझे यह कहने का जिद्द हुआ है कि वन विभाग के अन्तर्गत आयोजनागत पक्ष की " वन विभाग के आवासीय तथा अबावासीय भवनों का निर्माण" योजना के लिए चालू वित्तीय वर्ष में अदम्य धनराशि के साथै संलग्न तालिका में अंकित विवरण अनुसार रु० 2,57,21,000/- (रु० दो करोड़ सत्तावन हजार इक्कीस हजार मात्र) के अनुमोदित कार्यों/आगणनों के अनुसार कार्य कराने/व्यय हेतु श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति निम्न शर्तों एवं परिस्थितियों के अधीन प्रदान करते हैं:-

1. उक्त स्वीकृत वन चालू योजनाओं पर ही किया जाये और किसी भी दशा में उक्त धनराशि का उपयोग नये कार्यों के कार्यान्वयन के लिए न किया जाय. विभिन्न मदों में व्यय से पूर्व वित्त अनुभाग-1 के शासनादेश सं०-255/XXVII(1)/2007, दिनांक 26 मार्च, 2007 तथा पत्र संख्या-599/XXVII(1)/2007, दिनांक 12 जुलाई, 2007, द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुसार सक्षम स्तर की अनुमति/यथा स्थिति शासन का अनुमोदन प्राप्त कर ही किया जाये. निर्माण कार्य सम्बन्धी आगणनों पर सक्षम स्तर का अनुमोदन पूर्व में ही प्राप्त कर लिया जाय तथा यथा आवश्यकता नियमानुसार प्रशासनिक स्वीकृति पत्रक से प्राप्त की जाय. सम्भावित व्यय की फेंजिंग (बिमास के आधार पर) तथा अन्य सूचनाएँ एवं विवरण सम्बन्धित आधार पर शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय. किसी भी शासकीय व्यय हेतु भण्डार क्रय प्रक्रिया (स्टोर परचेज कन्ट्रोल) वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-1 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन नियम) वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-पांच भाग -1 (लेखा नियम) आय-व्यय सम्बन्धी नियम (वजट मैनुअल), सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के शासनादेश तथा अन्य सुसंगत नियम, शासनादेश आदि का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय.
2. योजना की विभिन्न मदों पर व्यय शासन के वर्तमान नियमों एवं आदेशों के अनुसार ही किया जाये तथा जहाँ आवश्यकता हो सक्षम अधिकारी/शासन की पूर्व सहमति/स्वीकृति ली जाय. गतिव्ययता के सम्बन्ध में नियमों का कड़ाई से पालन किया जाय. यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि सम्बन्धित निर्माण कार्य वन संरक्षण एवं विकास सम्बन्धी उद्देश्यों की पूर्ति करते हों.
3. शासन को प्रस्तुत/अनुमोदित आगणन में उल्लिखित दरें केवल आगणन गति के लिये ही अनुगन्ध हैं. कार्य कराने से पूर्व दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को तथा जो दरें शिफ्टूल ऑफ रेट में स्वीकृत नहीं हैं, अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता से अनुमोदन करना आवश्यक होगा. तदोपरान्त ही आगणन की स्वीकृति मान्य होगी.
4. कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र गति कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्ता करनी होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के किसी भी दशा में कार्य को प्रारम्भ न किया जाय.
5. कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितनी राशि की स्वीकृत की गई है, स्वीकृत नाम से अधिक व्यय कदापि न किया जाय.
6. एक मुश्त प्राविधान को कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गति कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त कार्य टेकअप किया जाय.
7. कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएँ तकनीकी दृष्टि को मध्य नजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरें/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पन्नित करना सुनिश्चित करें.

क्रमशः.....2

8. कार्य करना से पूर्व स्थल का भली-भाँति निरीक्षण उच्च अधिकारियों एवं भुगर्ववेत्ता के साथ अवश्य करा ले। निरीक्षण के पश्चात स्थल आवश्यकतानुसार निर्देशों तथा निरीक्षण टिप्पणी के अनुरूप कार्य किया जाय, साथ ही निर्माण में भूकम्परोधी तकनीकी व डिजाइन का उपयोग किया जाय और भवनों हेतु रोलर पेंसिव वास्तुकला का उपयोग भी किया जाय, जिस हेतु उरेहा से परामर्श प्राप्त किया जा सकता है।
9. निर्माण सामग्री को प्रयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला में अवश्य करा ले जाय तथा उपयुक्त पायी जाने वाली सामग्री को ही प्रयोग में लाया जाय।
10. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं०-2047/XIV-219 (2006) दिनांक 30 मई, 2006 द्वारा निर्गत आदेशों के क्रम में कार्य करते समय अथवा आगमन गति करते समय कड़ाई से पालन करने का कष्ट करें।
11. धनराशि का अहरण यथा आवश्यकता ही किया जाय।
12. टी०ए०सी० द्वारा परीक्षित आगमन की एक प्रति शासनादेश के साथ संलग्न कर इस आशय से प्रेषित है कि आगमन की प्रति निर्माण इकाई को भी उपलब्ध कराई जाय ताकि निर्माण इकाई आगमन के अनुसार निर्माण कार्य सम्पादित करा सके।
13. स्वीकृत वीर जा रही धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र महालेखाकार एवं शासन के वित्त विभाग को भी वर्षांत तक अवश्य उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।
14. अप्रयुक्त धनराशि बजट मैनुअल के प्रावधानों के अन्तर्गत समय सारणी के अनुसार समर्पित किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

2. इस सम्बन्ध में हो रहे वाला कार्य चालू वित्तीय वर्ष 2007-08 के आय-व्यय अनुदान संख्या-27 के लेखा शीर्षक 4406-वाचिकी तथा अन्य जीव पर पूंजी परिवर्धन 01-वाचिकी 101- वन संरक्षण और विकास 04-"वन विभाग के आवासीय तथा आवासीय भवनों का निर्माण" योजना के अन्तर्गत शासनादेश सं०-3652/X-2-2007-12(11)/2007 दिनांक 10 सितम्बर, 2007 द्वारा विभिन्न गतों में स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष किया जायेगा।

3. ये आदेश वित्त विभाग की अशासकीय संख्या-464(P)/XXVII(4)/2007, दिनांक 13 फरवरी, 2008 द्वारा प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

आवदीय

(आर०के० गिग)
अपर सचिव

संख्या-6725(1)/X-2-2007, चट्टीगढ़िया।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार(लेखा एवं लेखा परीक्षा), उत्तराखण्ड, ओवरस मोटर्स बिल्डिंग, सहारनपुर रोड, माजरा, देहरादून।
2. प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. सचिव, नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
4. अपर सचिव, वित्त अनुभाग-4, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
5. निजी सचिव, माननीय मुख्य मंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन।
6. निजी सचिव, माननीय वन एवं पर्यावरण मंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन।
7. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
8. आयुक्त, भद्रवाल/कुमाऊँ मण्डल, उत्तराखण्ड।
9. सम्बन्धित जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
10. निदेशक, कोषागार एवं वित्त संचालन, देहरादून।
11. मुख्य/परिष्ठा/सम्बन्धित कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
12. बजट राजव्यवस्था नियोजन एवं संसाधन, सचिवालय, देहरादून।
13. प्रभारी, एन.आई.सी., उत्तराखण्ड सचिवालय, देहरादून।
14. आई पत्राई (जी)।

(आर०के० गिग)
अपर सचिव

६५०

(धनराशि रु० हजार में)

क्र०सं०	कार्यालय का नाम	भवन का विवरण	विभाग की प्रस्तावित मांग	शासन द्वारा अनुमोदित लागत
1	2	3	4	5
1	प्र०व०, इंदरगढ़ का प्रभाग	आवासीय कालोनी इन्दिरा नगर टाईप-6 का 1 आवास, टाईप-5 स्पेशल का 1 आवास, टाईप-4 के 2 आवास, टाईप-3 के 5 आवास, विद्युतीकरण, जलमल व्यवस्था, आकस्मिक व्यय	8560	8345
2	प्र०व०, देहरादून का प्रभाग	इन्द्रानगर फॉरेस्ट कालोनी में ग्राउण्ड्रीवाल एवं स्थल विकास हेतु	3438	3145
3	प्र०व०, रुद्रप्रयाग का प्रभाग	रुद्रप्रयाग में टाईप-11 आवासों का निर्माण-4 आवास रुद्रप्रयाग का प्रभाग के मुख्यालय एवं आवासीय कालोनी का निर्माण	2613 12366	2439 11792
		योग	26977	25721

(रु० दो करोड़ अक्षतवन लाख इक्कीस हजार मात्र)

(आर०के० मिश्र)
अपर सचिव